International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 2-02-2026, Accepted: 01-03-2026, Published: 14-03-2026
Volume 12, Issue 1, 2026, Page No. 330-335

बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य में सार्क की प्रासंगिकताः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. अमित कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक अध्ययन विभाग, शिवहर्ष किसान पी. जी. कॉलेज, बस्ती, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना को लगभग चार दशक बीत चुके हैं, फिर भी यह क्षेत्र वैश्विक पटल पर सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। वर्तमान भू–राजनीतिक परिदृश्य में सार्क की प्रासंगिकता एक गहन विश्लेषणात्मक बहस का विषय है, जहाँ एक ओर साझा सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक समानताएं सहयोग के लिए एक अनुकूल आधार प्रस्तुत करती हैं, वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक विवाद, राजनीतिक अविश्वास और संस्थागत सीमाएं इसके मार्ग में अभेद्य दीवार बनकर खड़ी हैं । विशेष रूप से 2014 के काठमांडू शिखर सम्मेलन के पश्चात से सार्क लगभग एक निष्क्रिय अवस्था में है, जिसका प्राथमिक कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य जारी कूटनीतिक तनाव और सीमा पार आतंकवाद है। हाल के वर्षों में क्षेत्रीय परिदृश्य में अत्यंत तीव्र गति से बदलाव आए हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन और डॉ. मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा सार्क को पुनर्जीवित करने के मुखर प्रयासों ने इस संगठन के भविष्य को लेकर एक नई उम्मीद जगाई है। इसके समानांतर, चीन जैसे बाह्य राष्ट्रों का बढ़ता भू–आर्थिक प्रभाव, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच उभरता नया शीत युद्ध, और बिम्सटेक (BIMSTEC) जैसे वैकल्पिक क्षेत्रीय मंचों का तेजी से उदय सार्क के अस्तित्व के लिए नई चुनौतियाँ और अवसर दोनों उत्पन्न कर रहा है। यह विश्लेषणात्मक अध्ययन सार्क की वर्तमान स्थिति, क्षेत्रीय असंतुलन की संरचना, बांग्लादेश और पाकिस्तान की विदेश नीति के प्रभावों, और संगठन के समक्ष उपस्थित व्यापक चुनौतियों का गहराई से मूल्यांकन करती है। अंत में, यह रिपोर्ट यूरोपीय संघ (EU) और आसियान (ASEAN) के श्प्रकार्यवादश (Functionalism) मॉडल पर आधारित कुछ व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करती है, जिनके माध्यम से सार्क को 21वीं सदी की भू–राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप ढाला जा सकता है और इसे एक मृतप्राय संगठन से एक जीवंत क्षेत्रीय तंत्र में बदला जा सकता है।

मुल शब्दः प्रकार्यवाद, भू–राजनीति, नव–यथार्थवाद, सुरक्षा दुविधा, बिग ब्रदर सिंड्रोम, उच्च–संरक्षणवाद

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को आर्थिक विकास, शांति, और भू–रणनीतिक स्थिरता का एक प्रमुख साधन माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, वैश्विक स्तर पर यह स्वीकार किया जाने लगा कि व्यापार केवल शून्य–योग (zero sum) का खेल नहीं है, बल्कि यह अंतर–राज्यीय संबंधों को मजबूत करने और शांति स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दक्षिण एशिया में इस दिशा में विचार–विमर्श की जड़ें ऐतिहासिक हैं। इस क्षेत्र में एकीकरण के शुरुआती प्रयास 1947 के एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस (नई दिल्ली), 1950 के बगुइओ कॉन्फ्रेंस (फिलीपींस), और 1954 के कोलंबो पॉवर्स कॉन्फ्रेंस में देखे जा सकते हैं।

हालांकि, दक्षिण एशिया के लिए एक समर्पित क्षेत्रीय निकाय का पहला ठोस खाका 1970 के दशक के अंत में तैयार हुआ। बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने 1977 से 1980 के बीच भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की कई कूटनीतिक यात्राएं कीं और आसियान (ASEAN) के समान एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय निकाय के विचार पर चर्चा की। तदुपरांत, 2 मई 1980 को राष्ट्रपति रहमान ने सभी दक्षिण एशियाई देशों के प्रमुखों को एक पत्र लिखकर क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक आधिकारिक ढांचा स्थापित करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा।

प्रारंभ में, क्षेत्र के दो सबसे बड़े देशोंकृभारत और पाकिस्तानकृने इस प्रस्ताव को गहरे संदेह की दृष्टि से देखा। भारत को यह आशंका थी कि इस प्रस्तावित दक्षिण एशियाई मंच का उपयोग छोटे पड़ोसी देश भारत पर सामूहिक दबाव डालने और द्विपक्षीय मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए कर सकते हैं। यह शीत युद्ध का दौर था और सोवियत संघ के अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप के कारण भारत को यह भी भय था कि यह अमेरिका समर्थित कोई चाल हो सकती है। दूसरी ओर, पाकिस्तान का मानना था कि यह छोटे देशों को एकजुट कर क्षेत्र में भारतीय आधिपत्य और आधिपत्यवादी रणनीति को वैध बनाने का एक कूटनीतिक प्रयास है। इन प्रारंभिक आशंकाओं को दूर करने के लिए, बांग्लादेश ने एक ऐसा मसौदा तैयार किया जो सुरक्षा मामलों और विवादास्पद राजनीतिक मुद्दों से पूरी तरह मुक्त था, और केवल गैर–राजनीतिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित था। अंततः, इन कूटनीतिक प्रयासों के परिणामस्वरूप 8 दिसंबर 1985 को ढाका में पहले शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क की विधिवत स्थापना हुई।

वर्तमान में इस संगठन में आठ सदस्य राष्ट्र शामिल हैंरू अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। जनसांख्यिकीय और आर्थिक दृष्टिकोण से दक्षिण एशिया वैश्विक पटल पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सार्क देशों का कुल क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक विस्तार का लगभग 3 प्रतिशत (लगभग 2 मिलियन वर्ग मील) है, परंतु यहाँ विश्व की 21 प्रतिशत से 25 प्रतिशत आबादी (लगभग 2 अरब लोग) निवास करती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क क्षेत्र का योगदान लगभग 4.2 प्रतिशत से 5.2 प्रतिशत (लगभग 3.6 से 5.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) के बीच है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 'नव–यथार्थवाद' (Neorealism) सिद्धांत के माध्यम से दक्षिण एशिया की इस जटिल भू–राजनीतिक गतिशीलता को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार, राष्ट्र–राज्य अपने राष्ट्रीय हितों से प्रेरित तर्कसंगत प्राथमिक अभिनेता होते हैं। सार्क के भीतर भारत की विशालता से उत्पन्न प्रभुत्व की धारणा सहयोग के स्थान पर स्व–सहायता (self help) व्यवहार और सुरक्षा दुविधाओं (Security Dilemmas) को जन्म देती है । इसके विपरीत, 'प्रकार्यवाद' (Functionalism) का सिद्धांत यह तर्क देता है कि यदि राज्य राजनीतिक विवादों को दरकिनार कर तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग करें, तो इसके सकारात्मक परिणाम अंततः राजनीतिक एकीकरण का

मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं । सार्क का अब तक का इतिहास इन दो सिद्धांतों के बीच के संघर्ष की ही कहानी है।

2. क्षेत्रीय असंतुलन की वर्तमान स्थिति–

सार्क की संरचनात्मक विफलता और क्षेत्र की कम एकीकरण दर का एक सबसे प्रमुख कारण इस क्षेत्र में व्याप्त भारी जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सैन्य असंतुलन है। क्षेत्रीय सहयोग व्यवस्थाओं (Regional Cooperation Arrangements & RCAs) की सफलता काफी हद तक सदस्य देशों के बीच शक्ति संतुलन पर निर्भर करती है। दक्षिण एशिया के संदर्भ में, यह शक्ति संतुलन पूरी तरह से विषम है, जो क्षेत्रीय एकीकरण के मार्ग में एक मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक बाधा उत्पन्न करता है।

दक्षिण एशिया की राजनीतिक अर्थव्यवस्था भारत के इर्द–गिर्द घूमती है। भारत की अर्थव्यवस्था, भौगोलिक विस्तार और जनसंख्या अन्य सभी सात सार्क सदस्य देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था और जनसंख्या से तीन गुना से भी अधिक है। इस विषमता को आर्थिक आंकड़ों से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है; दक्षिण एशिया की कुल जीडीपी (लगभग 5.2 ट्रिलियन डॉलर) में से लगभग 86 प्रतिशत (लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर) का योगदान अकेले भारत का है । इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का 84 प्रतिशत से अधिक हिस्सा केवल भारत को प्राप्त होता है, जिससे अन्य छोटे सदस्य देशों में पूंजी और निवेश की भारी कमी बनी रहती है। व्यापार के मामले में भी, सार्क देशों के बीच होने वाले 5 बिलियन डॉलर के क्षेत्रीय व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 76 प्रतिशत (3.8 बिलियन डॉलर) है।

भौगोलिक केंद्रियता, जनसांख्यिकीय विशालता, सैन्य शक्ति और वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव के कारण भारत की यह स्थिति पड़ोसी देशों में "बिग ब्रदर" (Big Brother) सिंड्रोम को जन्म देती है। छोटे राष्ट्रों (जैसे नेपाल, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश) में अक्सर यह भू–राजनीतिक भय बना रहता है कि भारत सार्क मंच का उपयोग अपने क्षेत्रीय आधिपत्य को मजबूत करने, उनकी संप्रभुता को सीमित करने और उनकी कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं पर हावी होने के लिए कर सकता है। इस गहरी आशंका के परिणामस्वरूप, कई सदस्य देश भारत के साथ पूर्ण व्यापारिक उदारीकरण करने से बचते हैं और सार्क द्वारा पारित समझौतों (जैसे मोटर वाहन समझौता) को लागू करने में स्पष्ट अनिच्छा प्रदर्शित करते हैं।

इस क्षेत्रीय असंतुलन को दक्षिण एशिया के अनसुलझे सीमा और जल विवाद और भी अधिक जटिल बना देते हैं। इस क्षेत्र का इतिहास भारत–केंद्रित विवादों से भरा पड़ा है, जो क्षेत्रीय अविश्वास (Trust Deficit) को गहरा करते हैं। इन विवादों में भारत–पाकिस्तान के बीच कश्मीर और सर क्रीक विवाद, भारत–नेपाल के बीच कालापानी और सुस्ता विवाद, और भारत–बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारा, फरक्का बांध और न्यू मूर द्वीप (यद्यपि अब काफी हद तक सुलझ चुका है) विवाद प्रमुख रहे हैं।

सर क्रीक विवाद क्षेत्रीय असंतुलन और कूटनीतिक गतिरोध का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध के बीच स्थित 96 किलोमीटर लंबा दलदली ज्वारीय मुहाना है। पाकिस्तान 1914 के बॉम्बे सरकार के एक प्रस्ताव का हवाला देते हुए पूरे क्रीक पर दावा करता है, जबकि भारत 1925 के मानचित्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून के 'थलवेग सिद्धांत' (Thalweg Principle) के आधार पर मुहाने के मध्य–चौनल को सीमा मानता है । वर्तमान में, जलवायु परिवर्तन और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि (Sea Level Rise) ने सर क्रीक की स्थलाकृति को नाटकीय रूप से बदल दिया है, जिससे ज्वारीय चौनल की स्थिति अस्थिर हो गई है और एक नए सिरे से सर्वेक्षण की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है । इस तरह के विवादों के कारण न केवल दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच तनाव बना रहता है, बल्कि यह सार्क के मंच पर भी अविश्वास की छाया डालता है। जब तक सार्क सदस्य देशों के बीच ऐसे द्विपक्षीय राजनीतिक, क्षेत्रीय और सुरक्षा विवाद अनसुलझे रहेंगे, तब तक सार्क एक साझा क्षेत्रीय पहचान (Sense of Region) और "हम" की भावना स्थापित करने में विफल रहेगा ।

3. बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्षेत्रीय संतुलन पर प्रभाव–

सार्क के अतीत, वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करने में पाकिस्तान और बांग्लादेश की विदेश नीतियां और आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। जहाँ एक ओर पाकिस्तान के साथ भारत की निरंतर शत्रुता ने संगठन को संस्थागत लकवे का शिकार बना दिया है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में 2024 के सत्ता परिवर्तन ने इसके पुनरुद्धार की एक नई, यद्यपि जटिल, सुगबुगाहट पैदा की है।

पाकिस्तान की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से भारत की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने, उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को चुनौती देने और भारतीय प्रभाव को नियंत्रित करने के इर्द–गिर्द केंद्रित रही है। सार्क की वर्तमान अकर्मण्यता का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष कारण भारत–पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता और विश्वास की भारी कमी है। भारत के दृष्टिकोण से, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इस तनाव का सबसे विनाशकारी प्रभाव सार्क के नेतृत्व सम्मेलनों पर पड़ा है; यही कारण है कि 34 वर्षों के इतिहास में राष्ट्राध्यक्ष केवल 18 बार ही मिल पाए हैं।

इस कूटनीतिक गतिरोध का चरम बिंदु 2016 में आया, जब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 19वां सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित होना था। उसी वर्ष भारत में हुए उरी आतंकी हमले (जिसमें 19 भारतीय सैनिक मारे गए थे) के बाद, भारत ने आतंकवाद को कारण बताते हुए सम्मेलन का पूर्ण बहिष्कार कर दिया। भारत के इस कड़े रुख के बाद बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी किनारा कर लिया, जिससे सम्मेलन रद्द हो गया। तब से लेकर आज तक सार्क का कोई भी शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका है।

हाल के घटनाक्रमों ने इस खाई को और चौड़ा कर दिया है। अप्रैल 2025 में भारतीय प्रशासित कश्मीर के पहलगाम में हुए एक भीषण आतंकी हमले में 25 नागरिक मारे गए। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव इस स्तर तक बढ़ गया कि भारत ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी सैन्य कदम उठाए। तीन दिनों के सैन्य अभियानों और अत्याधुनिक ड्रोन युद्ध प्रणाली के उपयोग के बाद, 10 मई 2025 को दोनों देश युद्ध के कगार से लौटते हुए युद्धविराम पर सहमत हुए। इस हिंसक घटनाक्रम ने सार्क की प्रभावशीलता को पूरी तरह से पंगु बना दिया। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को "विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय" रूप से रोका नहीं जाता, तब तक सिंधु जल संधि जैसी महत्वपूर्ण साझा व्यवस्थाएं भी ठंडे बस्ते में रहेंगी।

पाकिस्तान के असहयोगात्मक रवैये ने प्रत्यक्ष रूप से सार्क की क्षेत्रीय आर्थिक और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को भी भारी नुकसान पहुँचाया है। सार्क मोटर वाहन समझौता (MVA), जिसका उद्देश्य माल और यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना था, और भारत द्वारा प्रस्तावित 'सार्क उपग्रह परियोजना' (SAARC Satellite) को पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण ही अवरुद्ध किया गया था। इसके अलावा, 2004 में

हस्ताक्षरित श्साफ्टाश (SAFTA) समझौते के तहत व्यापार बाधाओं को दूर किया जाना था, लेकिन पाकिस्तान ने इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भारत से आयात पर कड़ी नकारात्मक सूचियां लागू कर रखी हैं। इस हठधर्मिता का आर्थिक नुकसान स्वयं पाकिस्तान को भी उठाना पड़ता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक अध्ययन के अनुसार, इन व्यापार प्रतिबंधों के कारण लगभग 32 प्रतिशत पाकिस्तानी निर्यात और 50 प्रतिशत भारतीय निर्यात तीसरे देशों के माध्यम से होता है, जिससे पाकिस्तान को सालाना 400 से 900 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त नुकसान होता है क्योंकि उसे वही भारतीय वस्तुएं महंगे वैकल्पिक स्रोतों से आयात करनी पड़ती हैं।

इसके विपरीत, सार्क के संस्थापक राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश ने हमेशा इस संगठन को मजबूत करने में एक केंद्रीय और सकारात्मक भूमिका निभाने का प्रयास किया है । 2024 और 2025 के घटनाक्रमों ने एक बार फिर बांग्लादेश को क्षेत्रीय कूटनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। जुलाई और अगस्त 2024 में बांग्लादेश में एक अभूतपूर्व जन–आंदोलन (जुलाई क्रांति) हुआ, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से 'जेनरेशन ज़ेड' (Generation Z) और छात्रों ने किया। इस हिंसक विद्रोह के परिणामस्वरूप तत्कालीन सत्तावादी प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके पश्चात नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ।

शेख हसीना की सत्ता से बेदखली ने दक्षिण एशिया में एक नए भू–राजनीतिक विमर्श को जन्म दिया। अपने इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने आरोप लगाया कि अमेरिका बंगाल की खाड़ी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए श्सेंट मार्टिन द्वीपश (St-Martin's Island) की संप्रभुता मांग रहा था, और इनकार करने पर इस "विदेशी हाथ" (foreign hand) ने उनकी सरकार को गिरा दिया । यह आरोप दक्षिण एशिया में महाशक्तियों के बढ़ते दखल का संकेत देता है।

सत्ता संभालने के बाद, डॉ. यूनुस ने सार्क के पुनरुद्धार का पुरजोर आह्वान किया है। उन्होंने क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक 'बहु–गति' (multi speed) दृष्टिकोण, तटस्थ स्थानों पर बैठकों, और स्वतंत्र शांति समितियों के गठन का दूरदर्शी प्रस्ताव रखा है। कूटनीतिक संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से, डॉ. यूनुस ने दशकों के अविश्वास को पीछे छोड़ते हुए दिसंबर 2024 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के साथ मुलाकात की और 1971 के मुक्ति संग्राम से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने पर सहमति व्यक्त की। सार्क के वर्तमान महासचिव गोलाम सरवर (जो स्वयं बांग्लादेश से हैं) ने भी सार्क प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में बांग्लादेश की 'निर्णायक भूमिका' (Pivotal Role) की सराहना की है। फरवरी 2026 में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों सार्क देशों के बीच युद्ध किसी के हित में नहीं है, जो दर्शाता है कि बांग्लादेश क्षेत्रीय शांति के लिए सक्रिय रूप से चिंतित है।

हालाँकि, डॉ. यूनुस की यह क्षेत्रीय कूटनीतिक सक्रियता बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण बाधित हो सकती है। अंतरिम सरकार द्वारा शुरू किए गए संस्थागत सुधारों (न्यायपालिका, चुनाव प्रणाली) को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच गहरा मतभेद है। एक ओर जहाँ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) जल्द से जल्द चुनाव कराने और पुरानी प्रणाली बनाए रखने के पक्ष में है, वहीं जमात–ए–इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) चुनाव से पहले व्यापक प्रणालीगत सुधारों (जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व) की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार का राजनीतिक विखंडन डॉ. यूनुस की क्षेत्रीय पहलों को धीमा कर सकता है। फिर भी, बांग्लादेश का यह प्रयास यह स्पष्ट करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बंधक बने सार्क को गति देने के लिए क्षेत्रीय मध्य शक्तियों का मुखर हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है।

4. सार्क के समक्ष चुनौतियां एवं समस्याएं–

सार्क की संस्थागत असफलता किसी एक कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह संरचनात्मक खामियों, आर्थिक विषमताओं, कूटनीतिक अड़चनों और बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप का एक अत्यंत जटिल मिश्रण है। इन चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित है

- **आर्थिक विसंगतियां और व्यापारिक बाधाएं–**

विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, दक्षिण एशिया वर्तमान में विश्व का सबसे कम एकीकृत क्षेत्र है। सार्क देशों के बीच आपसी व्यापार क्षेत्र के कुल वैश्विक व्यापार का मात्र 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच है। इस निराशाजनक आंकड़े की तुलना जब आसियान (ASEAN) से की जाती है, तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। आसियान की जनसंख्या सार्क की जनसंख्या का लगभग एक–चौथाई है, फिर भी आसियान का कुल जीडीपी सार्क के लगभग बराबर (4 ट्रिलियन डॉलर) है और इसका वैश्विक निर्यात 1.9 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि सार्क का निर्यात मात्र 900 बिलियन डॉलर तक सीमित है। दक्षिण एशिया में इस कम एकीकरण के तीन मुख्य कारण हैं:

- **उच्च संरक्षणवाद (High Protectionism)**

दक्षिण एशियाई क्षेत्र विश्व के सबसे अधिक व्यापार संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। विशेष रूप से भारत, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, का 'एप्लाइड टैरिफ' दर (Applied Tariff Rate) लगभग 30.1 प्रतिशत रहा है, जो इसे समूह में सबसे कम मुक्त (least open) अर्थव्यवस्था बनाता है।

- **कमजोर रसद और बुनियादी ढांचा**

बंदरगाहों और परिवहन के बुनियादी ढांचे की खस्ता हालत, साथ ही नियामक बाधाएं (Non tariff barriers), व्यापार लागत को अत्यधिक बढ़ा देती हैं। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में देरी और सड़क/बंदरगाह की भीड़ निर्यातकों के लिए लेन–देन की लागत को असहनीय बना देती है। विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार, यदि दक्षिण एशिया अपने बुनियादी ढांचे की क्षमता को पूर्वी एशिया के स्तर के आधे तक भी ले आए, तो सार्क देशों के बीच आपसी व्यापार में 60 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि हो सकती है।

- **अनौपचारिक व्यापार (प्दवितउंस ज्तंकम) का बोलबाला:**

उच्च लेन–देन लागत, कड़े सीमा शुल्क और टैरिफ संरचनाओं में अंतर के कारण सार्क देशों के बीच बड़े पैमाने पर अनौपचारिक या अवैध व्यापार (Smuggling) होता है। कई मामलों में, जैसे भारत का भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ अनौपचारिक द्विपक्षीय व्यापार उनके आधिकारिक व्यापार के आंकड़ों से भी अधिक आंका गया है। उदाहरण के लिए, नेपाल में अपेक्षाकृत कम टैरिफ दरें विदेशी माल की तस्करी को बढ़ावा देती हैं। इसके अतिरिक्त, साफ्टा (SAFTA) के नियमों का दुरुपयोग करते हुए मलेशिया द्वारा नेपाल के रास्ते भारत में पाम ऑयल का अवैध निर्यात भी देखा गया है।

- **संस्थागत और संरचनात्मक सीमाएं–**

सार्क चार्टर के कुछ मूलभूत प्रावधान ही अनजाने में संगठन को पंगु बनाने का कार्य करते हैं। सार्क में सभी निर्णय श्सर्वसम्मतिश (Consensus) के आधार पर लिए जाते हैं, और किसी भी

द्विपक्षीय या विवादास्पद राजनीतिक मुद्दे को सार्क मंच पर उठाने की सख्त मनाही है। इस नियम का सीधा अर्थ यह है कि कोई भी एक सदस्य राष्ट्र (जैसे पाकिस्तान) केवल अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करके पूरी क्षेत्रीय परियोजना या समझौते को अनिश्चित काल के लिए बाधित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सार्क के पास विवाद समाधान का कोई भी प्रभावी संस्थागत तंत्र (Dispute Resolution Mechanism) नहीं है, जिसके कारण छोटे–मोटे मुद्दे भी दशकों तक अनसुलझे रह जाते हैं। इस संस्थागत अक्षमता के कारण ही सदस्य देशों का सार्क से मोहभंग हुआ है और उन्होंने क्षेत्रीयता के बजाय द्विपक्षीयवाद (Bilateralism) को तरजीह देना शुरू कर दिया है। संगठन को संसाधनों की भारी कमी का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि सदस्य देश अपने वित्तीय योगदान को बढ़ाने में लगातार अनिच्छा दिखाते हैं।

बाह्य शक्तियों का बढ़ता प्रभाव और 'नया शीत युद्ध'

दक्षिण एशिया की भू–राजनीति में चीन का आक्रामक प्रवेश सार्क के लिए एक अभूतपूर्व जटिलता बन गया है। भौगोलिक रूप से दक्षिण एशिया पूर्वी एशिया और मध्य पूर्व के तेल समृद्ध क्षेत्रों के मध्य स्थित है, जो इसे चीन के रणनीतिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है।

चीनी निवेश और बीआरआई (BRI)

अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे लगभग सभी प्रमुख सार्क सदस्य चीन की महत्वाकांक्षी 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) परियोजना का हिस्सा बन चुके हैं।

समांतर संगठनों का निर्माण

चीन 2005 से सार्क में एक पर्यवेक्षक देश है और उसने श्सार्क विकास निधिश (SDF) में 300,000 डॉलर का योगदान भी दिया है। वह लगातार सार्क की पूर्ण सदस्यता की मांग कर रहा है, जिसका भारत कड़ा विरोध करता है। इसके जवाब में, चीन ने 'माइनस–इंडिया' (भारत–रहित) कूटनीतिक पहल शुरू की हैं, जैसे कोविड–19 के दौरान श्चीन–दक्षिण एशिया आपातकालीन आपूर्ति रिजर्वश (China South Asia Emergency Supplies Reserve) और श्गरीबी उन्मूलन और सहकारी विकास केंद्रश। यह भारत के कूटनीतिक प्रभाव को कम करने की एक सीधी रणनीति है।

महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता

अमेरिका, चीन और रूस के बीच बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने दक्षिण एशिया को एक नए शीत युद्ध (New Cold War) के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। सदस्य देशों पर इन वैश्विक गुटों में शामिल होने का भारी दबाव है, जो सार्क की क्षेत्रीय अखंडता को विखंडित कर रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना द्वारा लगाए गए अमेरिकी हस्तक्षेप के आरोप और पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता बेदखली में कथित विदेशी खुफिया एजेंसियों की भूमिका, इस नए शीत युद्ध के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

वैकल्पिक क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय (सार्क बनाम बिम्सटेक)–

सार्क की विफलता और पाकिस्तान के अड़ियल रवैये ने भारत और अन्य देशों को क्षेत्रीय एकीकरण के लिए बिम्सटेक (BIMSTEC – बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी–सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) जैसे विकल्पों की ओर धकेल दिया है। भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' (Neighbourhood First) और 'एक्ट ईस्ट' (Act East) नीतियों के सामरिक अभिसरण ने बिम्सटेक को एक व्यावहारिक और आकर्षक विकल्प बना दिया है।

सार्क और बिम्सटेक का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर दोनों संगठनों की कार्यप्रणाली और वर्तमान स्थिति में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। भौगोलिक और जनसांख्यिकीय दायरे की बात करें तो सार्क में दक्षिण एशिया के 8 देश शामिल हैं जिनकी कुल आबादी लगभग 2 अरब है, जबकि बिम्सटेक एक व्यापक क्षेत्र को जोड़ता है जिसमें 7 देश (5 दक्षिण एशियाई और 2 आसियान देश) शामिल हैं। राजनीतिक मोर्चे पर, भारत और पाकिस्तान के बीच अनसुलझे विवादों और तनाव के कारण सार्क लगभग मृतप्राय हो चुका है और 2014 के काठमांडू शिखर सम्मेलन के बाद से इसका कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तान की अनुपस्थिति के कारण बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच संबंध आम तौर पर सौहार्दपूर्ण हैं। इस सकारात्मक माहौल का परिणाम यह है कि अप्रैल 2025 में बैंकॉक में बिम्सटेक का छठा शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जहाँ 'बैंकॉक विजन 2030' और समुद्री परिवहन समझौते पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर किए गए। अंततः, कनेक्टिविटी परियोजनाओं के मामले में भी सार्क का मोटर वाहन समझौता और सार्क उपग्रह परियोजना आपसी अविश्वास के कारण पूरी तरह से बाधित हैं, जबकि बिम्सटेक के तहत 'कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट' और 'एशियन ट्राइलेटरल हाईवे' जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर संतोषजनक प्रगति हो रही है।

भारत ने 2016 के बाद से सार्क को कूटनीतिक रूप से दरकिनार करते हुए जानबूझकर बिम्सटेक को बढ़ावा दिया है ताकि पाकिस्तान को क्षेत्र में अलग–थलग किया जा सके और बंगाल की खाड़ी में चीनी निवेश और प्रभाव को संतुलित किया जा सके। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के बजाय बिम्सटेक नेताओं को आमंत्रित कर इस कूटनीतिक बदलाव का स्पष्ट संकेत दिया था। अप्रैल 2025 में बैंकॉक में आयोजित 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भारत ने 21–सूत्रीय कार्य योजना (21–point action plan) प्रस्तुत की और एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप (EPG) की रिपोर्ट पर विचार किया, जो इस नए संगठन की परिपक्वता को दर्शाता है। यद्यपि बिम्सटेक कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग के मामले में बहुत आशाजनक है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह सार्क की पूर्ण रूप से जगह नहीं ले सकता क्योंकि इसमें दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण देश—अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव—शामिल नहीं हैं।

5. सार्क की उपलब्धियां: एक सूक्ष्म दृष्टिकोण

तमाम कूटनीतिक आलोचनाओं, राजनीतिक गतिरोधों और संस्थागत लकवे के बावजूद, यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि सार्क पूरी तरह से मृत हो चुका है। सार्क के छत्रछाया में स्थापित कई तकनीकी, विकासात्मक और शैक्षिक संस्थाएं आज भी पृष्ठभूमि में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं और क्षेत्रीय विकास में अपना योगदान दे रही हैं।

- **सार्क विकास निधि (SDF)**:

2010 में स्थापित सार्क विकास निधि (SDF) संगठन की सबसे सफल पहलों में से एक है। इसका उद्देश्य तीन विशिष्ट फाइनेंसिंग विंडोकृसामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचा—के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। आर्थिक विंडो ने गैर–टैरिफ बाधाओं को कम करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के विकास में मदद की है। हाल ही में, 20 नवंबर 2025 को कोलंबो (श्रीलंका) में एसडीएफ (SDF) के निदेशक मंडल की 41वीं बैठक आयोजित की गई, जहाँ भूटान के प्रतिनिधि को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

एसडीएफ ने 'द रीजनल एक्वालाइवलीहुड प्रोजेक्ट' (The Regional AquaLivelihood Project) और सार्क कृषि केंद्र (SAC) द्वारा बांग्लादेश के बोगुरा में 'आजीविका संवर्धन मूल्य–वर्धन परियोजना' जैसी कई जमीनी स्तर की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। इसके साथ ही, पाकिस्तान में महिला सशक्तिकरण के लिए करिश्मा अली फाउंडेशन और श्रीलंका में उद्यमशीलता के लिए नेविन्दरी प्रेमारत्ने जैसे युवा नेताओं को सार्क क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, जो इस मंच की सामाजिक प्रासंगिकता को सिद्ध करता है। कूटनीतिक हलकों और विशेषज्ञों (जैसे यूएसएआईडी (USAID) कटौती के संदर्भ में) द्वारा यह मांग की जा रही है कि एसडीएफ को अपने दायरे का विस्तार कर बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- **दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (SAU)**:

नई दिल्ली में स्थित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (South Asian University & SAU) सार्क की एक और बड़ी सफलता है जो शिक्षा के माध्यम से क्षेत्रीय सद्भाव को बढ़ावा दे रहा है । 2026 के शैक्षणिक सत्र में विश्वविद्यालय ने दाखिले में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है; उदाहरणतः, फरवरी 2025 में आयोजित 'बायोजेस्ट 2025' (BioZest 2025) विज्ञान महोत्सव में 'पॉलीग्लूटामाइन न्यूरोटॉक्सिसिटी' और 'ह्यूमन सेनेंसेंस मार्कर प्रोटीन' पर किए गए शोध कार्यों ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया।

- **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन** (SARSO):

व्यापारिक बाधाओं को दूर करने की दिशा में, 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन' (SARSO) ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्सो (SARSO) ने बिस्कुट, रिफाइंड चीनी, और डेयरी उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग और प्रसंस्करण के लिए सामान्य क्षेत्रीय नियामक मानक निर्धारित किए हैं। इन सामंजस्यपूर्ण मानकों (Harmonized Standards) के लागू होने से सदस्य देशों के बीच व्यापार लागत कम होगी और 'अनुरूप' (compliant) चिह्नित वस्तुओं को प्रयोगशाला परीक्षण के बिना सार्क देशों में निर्यात किया जा सकेगा। हाल ही में, अक्टूबर 2025 में वियतनाम के हनोई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन में सार्क महासचिव गोलाम सरवर ने भाग लिया, जो सार्क की वैश्विक कूटनीतिक उपस्थिति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, सर्सो ने 'अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट' (ANSI) के साथ मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

5. निष्कर्ष एवं सुझाव–

बदलते भू–राजनीतिक परिदृश्य, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और नए शीत युद्ध की आहट के बीच, दक्षिण एशिया के देशों के लिए क्षेत्रीय सहयोग कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अनिवार्यता है। यद्यपि बिम्सटेक (BIMSTEC) और आईओआरए (IORA) जैसे नए मंच उभर रहे हैं, लेकिन सार्क की भौगोलिक निरंतरता और ऐतिहासिक साझा सांस्कृतिक पहचान का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। फरवरी 2026 में काठमांडू में आयोजित सार्क प्रोग्रामिंग कमेटी के 62वें सत्र में महासचिव गोलाम सरवर और नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राई ने सदस्य देशों से "आकांक्षाओं को ठोस कार्रवाई में बदलने" का स्पष्ट आह्वान करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सार्क "दक्षिण एशियाई लोगों की साझा पहचान और भविष्य है"। सार्क को एक 'मृतप्राय' संगठन की स्थिति से उबारने और इसे 21वीं सदी के अनुकूल बनाने के लिए निम्नलिखित व्यावहारिक और रणनीतिक सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए:

- **'प्रकार्यवाद' मॉडल को अपनाना:**

सार्क की सबसे बड़ी विफलता इसके अत्यधिक राजनीतिकरण में निहित है। संगठन को यूरोपीय संघ (EU) के सफल ब्लूप्रिंट का अनुसरण करते हुए 'प्रकार्यवाद' के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इसका अर्थ है कि एक अधराष्ट्रीय (Supranational) संरचना का निर्माण किया जाए जहाँ आर्थिक निर्णयों को राजनीतिक विवादों से पूरी तरह अलग रखा जाए। जिस प्रकार यूरोप में कोयला और स्टील के व्यापार से शुरू हुआ सहयोग अंततः एक विशाल राजनीतिक और आर्थिक संघ में बदल गया (Spillover effect), उसी प्रकार सार्क को विवादित सीमाओं के बजाय जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऊर्जा व्यापार (जैसे TAPI और IP गैस पाइपलाइन) और आपदा प्रबंधन जैसे गैर–राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग से शुरुआत करनी चाहिए।

- **बहु–गति एकीकरण और उप–क्षेत्रीय सहयोग:**

सार्क चार्टर के 'सर्वसम्मति' (Consensus) नियम में संशोधन की तत्काल आवश्यकता है। यदि कोई एक देश (विशेष रूप से पाकिस्तान) किसी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पारगमन या व्यापार परियोजना का विरोध करता है, तो उसे वीटो करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके स्थान पर बहु–गति एकीकरण का मॉडल लागू किया जाना चाहिए, जहाँ जो देश सहयोग के लिए तैयार हैं, वे आगे बढ़ सकें। भारत द्वारा समर्थित BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) मोटर वाहन समझौता इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे सार्क के ढांचे के भीतर ही एक 'उप–क्षेत्रीय' विकल्प के रूप में और अधिक सशक्त किया जाना चाहिए।

संस्थागत सशक्तिकरण और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र: सार्क सचिवालय को केवल एक प्रशासनिक कार्यालय तक सीमित रखने के बजाय, इसे एक सक्षम, तटस्थ और अधिकार–संपन्न मध्यस्थ के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। वर्तमान में इसके पास संसाधन और कूटनीतिक अधिकार दोनों का अभाव है। इसके अतिरिक्त, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. यूनुस के सुझाव के अनुरूप, सार्क ढांचे के भीतर एक 'स्वतंत्र शांति और विवाद समाधान समिति' का गठन किया जाना चाहिए जो सदस्य देशों के बीच उठने वाले व्यापारिक और सीमा विवादों को हल करने के लिए एक संस्थागत मंच प्रदान कर सके।

डिजिटल और आभासी कूटनीति का अधिकतम उपयोग: जब भू–राजनीतिक तनावों या सुरक्षा चिंताओं के कारण शासनाध्यक्षों के भौतिक शिखर सम्मेलन आयोजित करना संभव न हो, तो कूटनीतिक बातचीत को पूरी तरह से रोकने के बजाय आभासी बैठकों और सम्मेलनों को प्राथमिकता देनी चाहिए । तदुपरांत, क्षेत्रीय थिंक–टैंक, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के बीच 'ट्रैक–टू' (Track Two) कूटनीति को लगातार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

भारत का रचनात्मक, उदार और उत्तरदायी नेतृत्व:

दक्षिण एशिया में भारत के विशाल आकार और भारी प्रभाव को देखते हुए, क्षेत्रीय एकीकरण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत पर ही है। भारत को श्गुजराल सिद्धांतश (Gujral Doctrine) की मूल भावना के अनुरूप एक उदार और गैर–पारस्परिक (non-reciprocal) नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए। छोटे पड़ोसी देशों के मन से 'बिग ब्रदर' सिंड्रोम को कम करने के लिए, भारत

को केवल उन व्यावहारिक कनेक्टिविटी और आर्थिक परियोजनाओं का वादा करना चाहिए जिन्हें वह समयबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक पूरा कर सके। साथ ही, भारत को क्षेत्र में अपने सामरिक हितों से समझौता करने वाली गतिविधियों के संबंध में स्पष्ट श्लाल रेखाएंश (Clear Red Lines) निर्धारित करनी चाहिए। अंततः, सार्क की प्रासंगिकता और इसका अस्तित्व इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके सदस्य देश—विशेषकर भारत और पाकिस्तान—इतिहास की कड़वाहटों, सुरक्षा दुविधाओं और संकीर्ण राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठकर एक साझे आर्थिक भविष्य की कल्पना कर पाते हैं या नहीं। जैसा कि सार्क सचिवालय द्वारा अत्यंत सटीक रूप से कहा गया है, "आसियान देशों के बीच भी गहरे द्विपक्षीय मतभेद और समस्याएं हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्रीय तंत्र को कभी ऐसे राजनीतिक संकटों का बंधक नहीं बनने दिया है"। बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य, 'नए शीत युद्ध' के खतरे और बाह्य शक्तियों के बढ़ते आर्थिक हस्तक्षेप को संतुलित करने के लिए, दक्षिण एशिया को सार्क जैसे एक मजबूत, स्वदेशी और समावेशी बहुपक्षीय मंच की तत्काल आवश्यकता है। आपसी अविश्वास, व्यापारिक संरक्षणवाद और भू–राजनीतिक हठधर्मिता की बेड़ियों को तोड़कर ही सार्क इस क्षेत्र के लगभग दो अरब लोगों की वास्तविक शांति, स्थिरता और समृद्धि का संवाहक बन सकता है।

संदर्भग्रंथ सूची

1. Kumar Ramesh, South Asian Zombie, the futility of reviving SAARC, Institute for Defense Studies and Analysis, 2018.
2. Khan Muhammad Rias, Investigating Crisis, South Asia lessons, evolving dynamics and trajectories, Stimson publishers, 2018.
3. Kanungo Kumar Anil, Regional integration in services in South Asia: Opportunities and Constraints, 55(2) pp 167-193, SAGE publications, 2018.
4. Ashraf Tahir Mian and Nassrudin, SAARC as a tool of regionalism in South Asia: Lessons from ASEAN, vol. 21, pp 4-25, ResearchGate, 2016
5. G. S. Parthia, An Enigma that is South Asia: India versus the region, Asia Pacific Review, 2013.
6. Raihan Selim and De Prabir, India-Pakistan Economic Cooperation: Implications for regional integration in South Asia, Commenwealth secretariat, 2013.
7. P.V Rao, South Asia retarded regionalism, Journal of the Indian Ocean Region, 2012.
8. https://www.orfonline.org/research/bimstec-seeks-to-succeed-where-saarc-failed.
9. https://www.tbsnews.net/thoughts/renewed-hope-saarc-956376.
10. Dubey, Muchkund. SAARC and South Asian Economic Integration. SAGE Publications, 2016. https://in.sagepub.com/en-in/sas/saarc-and-south-asian-economic-integration/book256176
11. Ghani, Ejaz. Reshaping Regionalism: The Case for BIMSTEC. Brookings Institution, 2021. https://www.brookings.edu/research/reshaping-regionalism-the-case-for-bimstec/
12. Jain, B.M. India and the South Asian Regional Order: The Interplay of Geopolitics and Economic Cooperation. Lexington Books, 2018. https://rowman.com/ISBN/9781498573455
13. Jha, Prem Shankar. BIMSTEC vs. SAARC: A Comparative Study of Regional Cooperation. Institute of South Asian Studies, National University of Singapore, 2022. https://www.isas.nus.edu.sg/papers/bimstec-vs-saarc-acomparative-study/
14. Kathuria, Sanjay. BIMSTEC and Trade Integration in South Asia. World Bank Publications, 2020. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32661.
15. https://maritimefairtrade.org/sir-creek-dispute-overview-origins-significance-and-key-aspects/.